मुख्यमंत्री ने चौंकाया 19 नए जिले और तीन संभागों की घोषणा कर के

पी.सी.सी. अध्यक्ष डोटासरा की मांग पर सीकर को संभाग बनाया, वहीं मालवीय को मजबूत करते हुए बांसवाड़ा भी संभाग बनेगा और पाली भी नया संभाग बना

- जयपुर में अब उत्तर - दक्षिण 2 जिले, वहीं जोधपुर में पूरब और पश्चिम 2 जिले होंगे।
- मुख्यमंत्री ने अपने सलाहकारों, रामकेश मीणा के विधानसभा क्षेत्र गंगापुर सिटी और बाबूलाल नागर के निर्वाचन क्षेत्र दूदू को भी जिला बनाया, रघु शर्मा की मांग पर केकड़ी जिला बना, पायलट समर्थक सुरेश मोदी को नीमकाथाना जिला मिला।

जयपुर, 17 मार्च (का.प्र.)। चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में पिछले 9 साल से लंबित नए जिलों के गठन की मांग को पूरा करते हुए 19 नए जिलों की घोषणा की है। इसी के साथ उन्होंने 3 नए संभाग भी घोषित किए हैं। अब राजस्थान में कुल 50 जिले होंगे, वही संभागों की संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। राजधानी जयपुर को भी उत्तर और दक्षिण जिलों के रूप में बांटा गया है। वही जोधपुर को पूरब और पश्चिम जिलों के रूप में बांटा गया है। वहीं अब लोग असमंजस में हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर उत्तर या जयपुर दक्षिण रहेगी या दोनों। यह असमंजस नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही समाप्त होगा। असमंजस यह भी है कि जयपुर में दो जिले के दो कलैक्टर, दो एस.पी. होंगे, तो क्या कमिश्नरेट भी दोहोंगे या कमिश्नरेट समाप्त किया जायेगा।

राजस्थान में वर्ष 2008 में वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रतापगढ़ को जिला बनाया था। उसके बाद से राजस्थान में नए जिलों के गठन की मांग उठती रही थी। इसको लेकर कई जगह धरने प्रदर्शन हो चुके थे और विधायकों की ओर से सरकार को मांग पत्र दिए गए थे। हाल ही जब रिटायर्ड आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ, तो कमेटी के पास 60 से ज्यादा जिलों के गठन के लिए मांग पत्र प्रस्तुत हुए थे। हालांकि 21 मार्च को राम लुभाया कमेटी का समय समाप्त होता, उससे पहले ही सरकार ने कमेटी का समय 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। उस समय माना जा रहा था कि नए जिलों की घोषणा फिलहाल नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अनुदान मांगों का जवाब देते हुए 19 नए जिले और तीन नए संभागों की घोषणा करते हुए सभी को चौंका दिया।

सीकर, बांसवाड़ा और पाली के रूप में तीन नए संभागों की घोषणा की गई। जिले की मांग को लेकर चप्पल - जूते पहनना छोड़ चुके विधायक मदन प्रजापत को संबोधित करते हुए गहलोत ने बालोतरा को जिला बनाने का ऐलान किया। उन्होंने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघवाल का भी नाम लिया और शाहपुरा व भीलवाड़ा को जिला बनाने की घोषणा की। गहलोत ने संभाग और जिलों के गठन के लिए शुरुआती तौर पर 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। श्रीगंगानगर जिले से अनूपगढ़, बाड़मेर जिले से बालोतरा, अजमेर से ब्यावर, भरतपुर जिले से डीग, नागौर जिले से डीडवाना-कुचामन, जयपुर जिले से दूदू, सवाई माधोपुर जिले से गंगापुर सिटी, अजमेर जिले से केकड़ी, जयपुर और अलवर जिले से कोटपूतली-बहरोड़, अलवर जिले से खैरथल, सीकर जिले से नीम का थाना, जोधपुर जिले से फलौदी, उदयपुर जिले से सलूंबर, जालौर जिले से सांचौर और भीलवाड़ा जिले से शाहपुरा नए जिले बनेंगे।

नए जिले और संभाग

नए जिले

1- अनूपगढ़
2- बालोतरा
3- ब्यावर
4- डीग
5- डीडवाना -कुचामन
6- दूदू
7- गंगापुरसिटी
8- जयपुर उत्तर
9- जयपुर दक्षिण
10- जोधपुर पूर्व
11- जोधपुर पश्चिम
12- केकड़ी
13- कोटपुतली बहरोड़
14- खैरथल
15- नीम का थाना
16- फलौदी
17- सलूम्बर
18- सांचौर
19- शाहपुरा

नए संभाग

1- बांसवाड़ा
2- पाली
3- सीकर

जिन 19 जिलों की घोषणा हुई है, उनमें से अभी 8 में अनूपगढ़, बहरोड़, फलोदी, शाहपुरा, ब्यावर, गंगापुर,दूदू और सलूंबर में कांग्रेस के विधायक नहीं है। हालांकि गंगापुर, दूदू और बहरोड़ से जीते निर्दलीयों ने सरकार को समर्थन दिया हुआ है। वही जयपुर जिले के दो हिस्सों की बात करें तो यहां पर अभी जिले का बंटवारा होने पर राजनीतिक स्थिति क्लियर होगी, लेकिन जिले में अभी भाजपा के चार विधायक हैं। यदि संभाग की बात करें, तो सीकर जिले में कांग्रेस के सभी विधायक जीते हैं। वही पाली संभाग के पाली जिले में कांग्रेस के पास एक भी विधायक नहीं है। संभाग घोषित किए गए बांसवाड़ा जिले में कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं। मुख्यमंत्री ने संभाग और जिलों की घोषणा करते हुए जहां अपने नजदीकी लोगों का पूरा ध्यान रखा है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दो समर्थक निर्दलीय विधायक और सलाहकार रामकेश मीणा और बाबूलाल नागर की विधानसभाओं को भी जिला बनाया गया है। सचिन पायलट समर्थक सुरेश मोदी की मांग पर नीम का थाना जिले का गठन हुआ है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मांग पर सीकर को संभाग घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री के नजदीकी उप सचेतक महेंद्र चौधरी के विधानसभा क्षेत्र से कुचामन को डीडवाना के साथ जिला बनाया गया है। मंत्री महेंद्रजीत मालवीय को मजबूत करते हुए बांसवाड़ा को भी संभाग बनाया गया है।

अखिलेश मिले ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ममता, दोनों ने प्रण किया है कि वे कांग्रेस रहित विपक्षी पार्टियों का एक ग्रुप बनाएंगे।

इन दोनों के भाजपा के खिलाफ एक एकीकृत विपक्ष के रूप में एक होने की दूर-दूर तक संभावना नहीं है क्योंकि इनमें एक तो यू.पी. में बुरी तरह हार चुका है और दूसरी पर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) नेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए भ्रष्टाचार का भारी दबाव है।

वास्तव में, अगर कोई बात है तो वह यह कि तृणमूल सरकार लड़खड़ाती प्रतीत होती है, क्योंकि उसके सभी शीर्ष नेता ई.डी. और सी.बी.आई. के महाजाल में फंसे हुए हैं। उनके लिए बचने का शायद ही कोई रास्ता हो क्योंकि उन्हें उनके घरों और अन्य पतों पर नोटों के ढेर के साथ पकड़ा गया था। बदनामी इतनी ही नहीं है, ऐजेन्सियों ने भारी संख्या में इतनी चल व अचल सम्पत्ति का पता लगाया है कि जिसकी गणना नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, एक आरोपी अनुब्रत मोण्डल के बॉडी गॉर्ड की पहचान रीयल एस्टेट्स के मालिक के रूप में की गई, जो 100 करोड़ रूपयों से अधिक का कारोबार था।

ममता बहुत अधिक बदनाम हो चुकी हैं और उनका राजनीतिक रिकॉर्ड अब इतना खराब है कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में उनके शायद ही कोई भूमिका निभाने की उम्मीद है। राहुल गांधी ने नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के विधानसभा चुनावों से पूर्व अपने चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की थी।

और, बंगाल से बाहर अपनी पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराने के अपने हताशापूर्ण प्रयासों के बावजूद वह बुरी तरह से विफल हुई हैं। वह त्रिपुरा में एक भी सीट नहीं जीत सकीं और ना ही किसी अन्य राज्य में कोई सेंध मार सकीं। मेघालय में कांग्रेस के जो पांच विधायक उनकी पार्टी में शामिल हुए थे, वे अब अपना राजनीतिक अस्तित्व खो चुके हैं।

उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में अपना जनाधार बढ़ा रही आम आदमी पार्टी (आप) एक सम्मानित विपक्षी पार्टी के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। वह बिना किसी शिष्टता के ममता बनर्जी को खारिज करती है।

भाजपा के विरूद्ध कांग्रेस को विपक्ष के खेमे से बाहर रखने के ममता के प्रमुख दृष्टिकोण का भी कोई तुक नहीं है। कांग्रेस आज की तारीख में भी भाजपा के खिलाफ देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। जैसी कि उम्मीद थी, ममता बनर्जी ने कहा है कि यह मानना ग़लत है कि कांग्रेस विपक्ष की "बिग बॉस" है। वास्तव में वह अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने को लेकर ही कांग्रेस का कद छोटा करने की दिशा में काम करती रही हैं।

ममता बनर्जी ने इससे पहले गोवा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की खरीद-फरोख्त की थी, जिसका उलटा असर हुआ क्योंकि विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य के जो नेता उनकी पार्टी में शामिल हुए थे, वे चुनाव के दिन से पहले ही कांग्रेस में लौट आए।

इसके बाद मेघालय में कांग्रेस के आधे विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, जिससे राज्य की कांग्रेस सरकार का तुरन्त प्रभाव से पतन हो गया था।

उसके बाद मेघालय में हुए विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह कांग्रेस के चुनावी जनाधार की मदद से यहां सत्ता पर काबिज हो जाएगी।, लेकिन ममता की पार्टी 5 सीटों को छोड़कर सभी पर चुनाव हार गई थी। इन पांच सीटों पर भी कांग्रेस छोड़कर टी.एम.सी. में आए नेताओं ने जैसे-तैसे जीत दर्ज की। इसलिए तृणमूल राज्य में सरकार गठित करने के आस पास भी नहीं पहुंच सकी।

'पहले संसद से बाहर माफी मांगें, फिर सदन में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चाहने से पहले, बाहर क्षमा याचना करनी चाहिये। शहज़ाद ने ट्वीट किया "दुख की बात है कि ईगो नं. 1 परिवार संसद की संस्था से ऊपर है।"

उन्होंने कहा कि राहुल ने विदेशी धरती पर विदेशी हस्तक्षेप की माँग करके हमारी सम्प्रमुता के खिलाफ एक घोर अपमानजनक टिप्पणी की है। अगर वे संसद को लेकर गंभीर है तो उन्हें संसद में सम्बल माँगने से पहले, तुरन्त ही बाहर माफी माँगनी चाहिये थे।

उन्होंने ट्वीट किया, "आप संसद की जड़ नहीं काट सकते तथा उसके शरण माँगिये । पहले माफी माँगे देश से।" भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी "राष्ट्र विरोधी टूलकिट" का स्थाई हिस्सा बन गये हैं।"

नड्डा ने समाचार एजेंसी ए एन आई से कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त होती जा रही है। राष्ट्र द्वारा बार-बार अस्वीकार कर दिये जाने के बाद, राहुल गांधी अब इस राष्ट्रविरोधी टूल-किट के स्थाई हिस्सा बन गये हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब राहुल गांधी ने "भारत के मामलों में एक अन्य देश के हस्तक्षेप की माँग की", उस समय उनका इरादा क्या था। इंग्लैंड में एक समारोह के दौरान, राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र के ढाँचे पर हमला हो रहा है तथा देश की संस्थाओं पर "पूरा-पूरा हमला" हो रहा है। भाजपा नेताओं तथा मोदी सरकार के मंत्रियों के इन आरोपों, कि इंग्लैंड यात्रा के दौरान गांधी के भाषण राष्ट्र-विरोधी थे, के बावजूद, शीर्षस्थ विशेषज्ञों द्वारा उनके संवादों के वीडियोज़ की बारीक संवीक्षा दर्शाती है कि उनमें ऐसा कुछ नहीं है, जिसे "राष्ट्र-विरोधी कहा जा सके।

इससे पूर्व, कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही किये जाने के लिये राज्य सभा के सभापति जगदीश धनकड़ को पत्र लिख दिया। उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी नेता सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी के खिलाफ "अनादरपूर्ण, अप्रिय तथा मानहानि कारक" टिप्पणियाँ की हें।

नियम 188 के तहत, सभापति को दिये गये अपने नोटिस में, वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री के 9 फरवरी के उस भाषण का हवाला दिया है, जो उन्होंने राष्ट्रपति के सम्बोधन के धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में दिया था।दरअसल, कांग्रेस ने मोदी पर आरोप लगाया था कि वे अपने भाषणों में नेहरू का उल्लेख नहीं करते, जिसके जवाब में, मोदी ने कहा था कि नेहरू का कोई भी वंशज नेहरू सरनेम नहीं लगाता है।

'छह दिन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के संरक्षण में पल रहे हैं। बच्ची को बरामद नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन की राह पकड़नी होगी।

ए.बी.वी.पी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपर सैशन न्यायालय के समक्ष एबीवीपी के छात्र गुलशन मीना, देव पलसानिया, महेश मीना, विष्णु कुमार, प्रमोद मीना और पीयूष चौधरी की ओर से अधिवक्ता आयुष मल ने जमानत के लिए प्रर्थाना पत्र पेश किया। इसमें कहा गया कि प्राथी सभी छात्र निर्दोष हैं।

'सोमवार से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिये बिना, लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के विरूद्ध टिप्पणी करके, नियम 352 भी तोड़ा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को दृढ़तापूर्वक कहा कि राहुल द्वारा माफी माँगे जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के उस बयान को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने राहुल को "राष्ट्र-विरोधी" बताया है, वहीं, राहुल, जो लोकसभा स्थगित हो जाने के बाद, संसद भवन पहुँचे थे, ने नड्डा के आरोप पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।

लन्दन में राहुल द्वारा की गई टिप्पणी के लिये, उन पर कड़ा प्रहार करते हुये नड्डा ने कहा था कि राहुल"राष्ट्रविरोधी टूल-किट" का स्थाई हिस्सा बन गये हैं।

नड्डा ने कहा था, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्तहो रही है। राष्ट्रद्वारा बार-बार खारिज कर दिये जाने के बाद, राहुल गांधी अब इस राष्ट्रविरोधी टूल-किट का स्थाई हिस्सा बन गये हैं।"

विपक्षी सांसदों संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष प्रदर्शन किया, जहाँ खड़गे ने कहा कि अड़ानी-प्रकरण की जाँच जॉइन्ट पार्लियामेन्ट्री कमेटी (जेपीसी) की माँग का दफ्न करने की भाजपा की कोशिश, राहुल के झूठं मुद्दे को उठाने से कारगर होने वाली नहीं हैं।

गहलोत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्यमंत्री को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। समझा जाता है कि सारे कर्ताधर्ता गहलोत ही है। यह साबित करना मुश्किल नहीं है कि सरकार ने ही फोन टैपिंग की अनुमति दी थी इससे मुख्यमंत्री, जो नए जिलों की घोषणा कर खुशी से झूम रहे हैं, को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908